

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं०-209
उत्तर देने की तारीख 06 दिसम्बर, 2013

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना

209. श्री राजीव चन्द्रशेखर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अभी तक ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़े ग्राम पंचायतों की संख्या सहित राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है;
- (ख) क्या यह सच है कि सरकार ने अक्टूबर, 2013 की अंतिम समय-सीमा को पार कर लिया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विलंब के क्या कारण हैं; और
- (घ) इसे किस समयावधि के भीतर कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क): भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (बीबीएनएल), जोकि राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन से गठित कंपनी है, ने ग्राम पंचायतों (जीपी) को कवर करते हुए तीन प्रयोगिक परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं। इन परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

- (i) अरियन ब्लॉक, जिला अजमेर, राजस्थान राज्य - भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा 30 ग्राम पंचायतों (जीपी) को लिंक करते हुए।
- (ii) पारवदा ब्लॉक, जिला विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश - पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा 15 ग्राम पंचायतों को लिंक करते हुए।
- (iii) पाणिसागर ब्लॉक, जिला उत्तरी त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य - रेलटेल द्वारा 15 ग्राम पंचायतों को लिंक करते हुए। प्रायोगिक परियोजनाएं 15.10.2012 को पूरी कर ली गई थीं।

इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने उपर्युक्त तीन ब्लॉकों में प्रयोक्ता सेवाएं मुहैया कराने के लिए एनओएफएन फाइबर के माध्यम से निम्नानुसार एक परियोजना कार्यान्वित की है:-

- सभी तीन ब्लॉकों और 60 ग्राम पंचायतों में 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई।
- स्कूलों, जन स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), जिला ज्ञान केंद्र (डीकेसी) सरकारी कार्यालयों आदि सहित 195 संस्थानों को प्रत्येक स्थान पर 10 मेगाबाइट बैंडविड्थ के साथ जोड़ा गया।
- सभी स्थानों पर कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस और वेबकैम उपलब्ध कराए गए।
- सेवाओं का एक विभाग अभिज्ञात किया गया और उसमें ई-लर्निंग, ई-मेडिसिन, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), मीसेवा और अन्य जी2जी, जी2सी और बी2सी सेवाओं सहित सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
- पंचायत स्तर तक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के प्रबंधन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रचालन प्रबंधक नियुक्त किया गया।